

## न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 06 / 2022

बउनवान

राजेन्द्र आयु 46 साल पुत्र श्री तोलाराम, जाति मीना, निवासी गजनपुरा, तहसील बारां जिला बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक  
2. पेरोकार सरकार


(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 30.06.2023

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 30.09.2021 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गजनपुरा तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 575, 570, 568 कुल रकबा 0.28 है., किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 154/- रुपये अर्थदण्ड एवं 45 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नहीं किया गया है एवं अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नहीं की है, और ना ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये हैं तथा बिना मौके पर कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर ठुड़ा है। अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 30.09.2021 निरस्त फरमावें।

  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोंडेंट को जर्ने सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समात कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।


दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 423/21 निर्णय दिनांक 05.02.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपील में अपीलांट ने अंकित किया है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 575, 570, 568 कुल रकबा 0.28 है0 ग्राम गजनुपरा पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 423/21 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 59/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



  
(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारां  
बारां (राज०)